



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 458]

नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 26, 2006/आश्विन 4, 1928

No. 458]

NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 26, 2006/ASVINA 4, 1928

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 सितम्बर, 2006

सा.का.नि. 593(अ).—केंद्रीय सरकार रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) की धारा 198 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :-

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय रेल (भारतीय रेल पर कंटेनर गाड़ियां चलाने के लिए ऑपरेटर को अनुज्ञा) नियम, 2006 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं :- इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो-

(क) "अधिनियम" से रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) अभिप्रेत है;

(ख) "ऑपरेटर" से कोई व्यक्ति, जिसने भारतीय रेल पर कंटेनर गाड़ियां चलाने के लिए अनुज्ञा ली है, अभिप्रेत है;

(ग) सभी अन्य शब्दों और पदों के, जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं किंतु अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो उस अधिनियम में हैं।

3. पात्रता :- कोई व्यक्ति या संयुक्त उद्यम या कंपनी अधिनियम, 1956 के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई कंपनी इन नियमों के अंतर्गत कंटेनर गाड़ियां चलाने के लिए अनुज्ञा लेने के पात्र हैं।

4. निर्यात-आयात यातायात :- निर्यात-आयात यातायात के लिए ऑपरेटर-

(क) कंटेनर गाड़ियों का प्रबंध करने के लिए भीतरी प्रदेशों या अंतर्देशीय अवस्थानों में पर्याप्त प्रबंध क्षमता सहित

रेल से संपर्क अंतर्देशीय कंटेनर डिपो तक उपयुक्त पहुंच रखेगा; या

(ख) रेल मंत्रालय से सैद्धांतिक रूप में अनुमोदन प्राप्त कर लेने के छः महीनों के भीतर विद्यमान रेल अंतर्देशीय कंटेनर डिपो ऑपरेटर से कंटेनर गाड़ियों के संचालन के लिए उसकी सुविधा का उपयोग करने के लिए रेल टर्मिनल ऑपरेटर एक करार करेगा, या

(ग) यह वचनबंध देगा कि वह कंटेनर गाड़ियां प्रचालन का सैद्धांतिक अनुमोदन मिलने के तीन वर्षों की अवधि के भीतर रेल सुविधा सहित अपने स्वयं के अंतर्देशीय कंटेनर डिपो का विकास करेगा।

5. घरेलू यातायात :- घरेलू यातायात के लिए ऑपरेटर :-

(क) कंटेनर गाड़ियों का प्रबंध करने के लिए दो भीतरी प्रदेशों या अंतर्देशीय अवस्थानों में पर्याप्त प्रबंध क्षमता सहित रेलवे से सम्पर्क वाले दो अंतर्देशीय कंटेनर डिपो तक उपयुक्त पहुंच रखेगा; या

(ख) रेल मंत्रालय से सैद्धांतिक अनुमोदन मिलने के छः महीने के भीतर विद्यमान रेल अंतर्देशीय कंटेनर डिपो ऑपरेटर या रेल टर्मिनल ऑपरेटर से कंटेनर गाड़ियों के संचालन के लिए उसकी सुविधा का दो अवस्थानों पर उपयोग करने हेतु एक करार करेगा; या

(ग) यह वचनबंध देगा कि वह कंटेनर गाड़ियां प्रचालन का सैद्धांतिक अनुमोदन मिलने के तीन वर्षों की अवधि के भीतर दो अवस्थानों पर रेल सुविधा वाले अपने अंतर्देशीय कंटेनर डिपो का विकास करेगा।

6. आवेदनकर्ता निम्नलिखित क्रियाकलापों में से किसी एक का अनुभव रखेगा :-

(i) परिवहन

(ii) व्यापार और वाणिज्य

- (iii) अवसंरचना
- (iv) माला/कार्गो का प्रबंध करना
- (v) पत्तन/भू-टर्मिनल प्रचालन
- (vi) संभार तंत्र
- (vii) भांडागारण
- (viii) विनिर्माण
- (ix) पट्टे पर देना

7. रेल कंटेनर प्रचालन का विनियमन.— भारतीय रेल नेटवर्क पर रेल कंटेनर ऑपरेटर के प्रवेश को विनियमित करने के क्रम में, गेटवे पत्तनों की आवश्यकता पूरी करने वाले विभिन्न रेल गलियारों पर अधिकांशतः विद्यमान और प्रत्याशित यातायात की मात्रा के आधार पर विभिन्न मार्गों को चार प्रवर्गों में बांटा गया है तथा ये प्रवर्ग इस प्रकार हैं :—

- (1) प्रवर्ग-I के अंतर्गत तुगलकाबाद, दादरी, गुडगांव आदि जैसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के जे.एन. पत्तन या मुंबई पत्तन की आवश्यकता पूरी करने वाले सभी विद्यमान या भावी अंतर्देशीय कंटेनर डिपो भी होंगे और इसके अंतर्गत घरेलू यातायात सहित ढंडारी कलां, मुरादाबाद आदि जैसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के रास्ते होकर पहुंचने वाले सभी गंतव्य अवस्थान भी शामिल हैं।
- (2) प्रवर्ग-II के अंतर्गत प्रवर्ग-I के अंतर्गत आने वाले स्थानों को छोड़कर जे.एन. पत्तन या मुंबई पत्तन की आवश्यकता पूरी करने वाले सभी विद्यमान या भावी अंतर्देशीय कंटेनर डिपो शामिल होंगे और इस प्रवर्ग में प्रवर्ग-I मार्गों के यातायात को छोड़कर सारा घरेलू यातायात भी शामिल होगा।
- (3) प्रवर्ग-III के अंतर्गत पिंपावाव, मुंद्रा चैन्ने, एन्नौर, विजाग तथा कोच्चि पत्तनों तथा उनके अंतर्देशीय अवस्थानों की आवश्यकता पूरी करने वाले सभी मौजूदा या भावी अंतर्देशीय कंटेनर डिपो शामिल होंगे और इस प्रवर्ग में प्रवर्ग-I में उल्लिखित मार्गों के यातायात को छोड़कर सारा घरेलू यातायात भी शामिल होगा।
- (4) प्रवर्ग-IV के अंतर्गत प्रवर्ग-I में वर्णित मार्गों के यातायात को छोड़कर सभी घरेलू यातायात सहित पोर्ट जैसे कांडला, न्यू मंगलौर, तूतीकोरीन, हल्दिया, कोलकाता, पारादीप और मुरमगांव पत्तन तथा उनके अंतर्देशीय प्रदेश शामिल हैं।

8. वित्तीय क्षमता.—(1) आवेदनकर्ता को वित्तीय क्षमता वार्षिक व्यापारावर्त या शुद्ध धन के रूप में 1 अरब रु. से कम नहीं होगी।

- (2) कंटेनर गाड़ियों के परिचालन के उद्देश्य से कई कंपनियों एक संकाय होने के मामले में, प्रत्येक घटक सदस्य का वार्षिक व्यापारावर्त या शुद्ध धन 50 करोड़ रु. से कम नहीं होगा।
- (3) ऐसी कोई कंपनी जो रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1985 के अधीन रुग्ण घोषित कर दी गई है कंटेनर गाड़ियां चलाने के लिए एकल रूप में या अन्य कंपनियों के सहयोग से इन नियमों के अंतर्गत आवेदन करने की पात्र नहीं होगी।

9. अनुमोदन प्रक्रिया.—(1) यदि प्रस्तावित ऑपरेटर को अंतर्देशीय कंटेनर डिपो का विकास करना है, तो अंतर्देशीय कंटेनर डिपो के साथ रेल संपर्क के लिए वह अंतर्देशीय कंटेनर डिपो की स्थापना और परिचालन के लिए भारत सरकार की अंतर-मंत्रालय समिति से अपेक्षित अनुज्ञा 6 मास के भीतर अवश्य प्राप्त करेगा।

(2) वह अपना आवेदन रेल मंत्रालय को यह उपदर्शित करते हुए जिसमें उसकी विधिक पहचान, कम से कम अगले पांच वर्षों के लिए परिचालन के आशयित विस्तार, इन नियमों में दर्शाए गए विभिन्न पात्रता मानकों के अनुपालन का प्रमाण तथा इन नियमों में निर्धारित तथा समय-समय पर संशोधित निबंधनों और शर्तों को स्वीकार करने की रजामंदी को अधिकथित करेगा।

(3) प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों तथा स्पष्टीकरण के आधार पर, यदि कोई हो, रेल "सैद्धांतिक अनुमोदन" प्रदान करेगी और भावी ऑपरेटर "सैद्धांतिक अनुमोदन" अनुदत्त होने के मामले में तीन वर्षों के भीतर रेल की समाधानप्रद रूप में कंटेनर गाड़ियों के परिचालन की तैयारी दर्शित करने में असफल रहता है, तो जब तक रेलवे द्वारा पूर्विक विस्तार प्रदत्त नहीं किया गया हो, व्यपगत माना जाएगा।

(4) परिचालन को प्रारंभ करने से पूर्व, ऑपरेटर रेल के साथ एक करार करेगा, जिसके अंतर्गत नई लाइनों या आस्तियों के स्वामित्व तथा अन्य संबंधित विवरण सहित विस्तृत परिचालनिक एवं लेखा प्रक्रिया भी होगी तथा रेल और ऑपरेटर के मध्य किसी भी प्रकार के विवाद को सुलझाने के लिए इस करार में उपयुक्त माध्यस्थम प्रक्रिया के उपबंध भी होंगे।

(5) यह अनुज्ञा प्रत्येक वर्ष पहले मास से आरंभ होगी।

10. रजिस्ट्रीकरण फीस.—(1) प्रत्येक आवेदनकर्ता कंटेनर गाड़ियां चलाने के लिए आवेदन प्रस्तुत करते समय प्रवर्ग-I जिसके अंतर्गत सभी मार्गों के लिए आवेदन करने के लिए पचास करोड़ रुपए और प्रवर्ग-I को छोड़कर प्रत्येक व्यक्तिगत प्रवर्ग के मार्गों के लिए दस करोड़ रु. की अप्रतिदेय रजिस्ट्रीकरण फीस जमा कराने की अपेक्षा होगी और केवल प्रवर्ग-I में उल्लिखित मार्गों के लिए आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

(2) आवेदकों की रजिस्ट्रीकरण फीस, जो पात्र नहीं पाए गए हैं, को बिना किसी ब्याज के प्रतिदेय कर दी जाएगी।

11. अनुज्ञा प्रदत्त करने की रूपात्मकता.—(1) प्रवर्ग-I के लिए अनुज्ञा के अंतर्गत पूरे देश में किन्हीं स्थानों के बीच गाड़ियां चलाने की अनुज्ञा और इसके अंतर्गत सभी अन्य प्रवर्गों की अनुज्ञा भी है तथा यदि ऑपरेटर किसी विशेष प्रवर्ग (प्रवर्ग-I को छोड़कर) के लिए आवेदन करता है, तो उसे प्रवर्ग-I के स्टेशनों को छोड़कर सभी मार्गों के आयात-निर्यात यातायात तथा घरेलू यातायात के लिए केवल उस प्रवर्ग के किसी भी स्थानों के बीच कंटेनर गाड़ियां चलाने की अनुज्ञा होगी।

(2) किसी भी मार्ग पर गाड़ियों की संख्या की कोई सीमा नहीं होगी।

12. निबंधन और शर्तें.—(1) विभिन्न ऑपरेटरों की कंटेनर गाड़ियों को किसी प्रकार की परिचालनिक अत्यावश्यकताओं और/या समय-समय लगाए गए प्रतिबंधों को देखते हुए सामान्यतः बिना किसी विभेद के 'पहले आओ, पहले पाओ' आधार पर प्रेषित किया जाएगा।

- (2) अंतर्देशीय कंटेनर डिपोओं को निजी साइडिंगों के समान माना जाएगा तथा निजी साइडिंगों के लिए अधिकथित नियम और प्रक्रियाएं उन पर भी यथावश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगी।
- (3) रेल के परिचालन के लिए भूमि और अन्य अपेक्षित सुविधाएं तथा निकटतम रेल शीर्ष से अंतर्देशीय कंटेनर डिपो का संपर्क स्थापित करने वाले रेलपथ ऑपरेटर को अपनी लागत पर उपलब्ध कराना होगा; परंतु यदि रेलवे भूमि उपलब्ध है, तो ऑपरेटर के आवेदन पर रेल भूमि की लाइसेंसिंग के लिए रेल मंत्रालय द्वारा निर्धारित सामान्य निबंधन और शर्तों पर मुहैया कराया जाएगा।
- (4) कंटेनरों के संचलन के लिए, ऑपरेटर अनुसंधान, अभिकल्प एवं मानक संगठन के अनुमोदित डिजाइन के अनुसार अपना स्वयं का चल स्टॉक और कंटेनर उपाप्त करेगा तथा चल स्टॉक का प्रवृत्त नियमों के अनुसार निरीक्षण किया जाएगा।
- (5) पत्तनों या अंतर्देशीय कंटेनर डिपो में कंटेनरों के लदान और उतराई का उत्तरदायित्व ऑपरेटर का होगा।
- (6) रेलपथ का अनुरक्षण ऑपरेटर द्वारा स्वयं अपनी लागत पर किया जाएगा और निरीक्षण या पर्यवेक्षण के लिए प्रभारों का भुगतान उसे विहित प्रचलित दरों के अनुसार भारतीय रेल को करना होगा और चल स्टॉक का अनुरक्षण भारतीय रेल द्वारा किया जाएगा, जिसके लिए विहित प्रभार ऑपरेटर से वसूल किए जाएंगे।
- (7) ऑपरेटर, भारतीय रेल को उसके किसी भी परिसर के निरीक्षण के लिए और रेलवे के परिचालन से संबंधित दस्तावेजों की संवीक्षा के लिए अनुज्ञात करेगा तथा वह इसके लिए सुविधाएं, जो ऐसा करने के लिए आवश्यक और उचित हों, उपलब्ध कराएगा।
- (8) ऑपरेटर मालभाड़ा दर सूची, लाल दर सूची और अधिनियम के उपबंधों में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन और समय-समय पर इस विषय पर रेल मंत्रालय द्वारा जारी अनुदेशों के आधार पर सभी प्रकार का माल ढो सकता है।
- (9) कंटेनरों और फ्लैटों का संचलन रेलवे द्वारा समय-समय पर अधिसूचित विभिन्न प्रकार के मालडिब्बों के लिए निर्धारित मानक आकार वाले ब्लॉक रेकों में होगा।
- (10) भारतीय रेल की मालभाड़ा परिचालन सूचना प्रणाली भी एकीकृत प्रबंधन और परिचालन सूचना सेवा के लिए ऑपरेटर की आवश्यकताओं को पूरा करेगी और मालभाड़ा परिचालन सूचना प्रणाली द्वारा अपेक्षित समस्त संबंधित डाटा, ऑपरेटर उपलब्ध कराएगा और उसे उचित दरों पर इस प्रणाली पर केवल 'रीड ओनली' एक्सेस उपलब्ध कराया जाएगा।

- (11) ऑपरेटर रेलवे द्वारा समय-समय पर अधिसूचित या नियत तथा सभी ऑपरेटरों पर समान रूप से लागू कर्षण प्रभार रेलवे को संदत्त करेगा।
- (12) कर्षण प्रभारों के संदाय के लिए वाणिज्य नियमावली और समय-समय पर जारी अन्य मार्ग निर्देशों का अनुसरण किया जाएगा।
- (13) प्रलेखीकरण कार्य, जिसके अंतर्गत कर्षण प्रभारों के लिए रेलवे रसीद जारी करना भी है, अंतर्देशीय कंटेनर डिपो में तैनात रेल कर्मचारियों द्वारा किया जाएगा और ऐसे कर्मचारियों की लागत ऑपरेटर को वहन करनी होगी तथा यह पृथक प्रभार्य होगा।
- (14) ऑपरेटर अपने ग्राहकों से रेल कर्षण, टर्मिनल प्रबंध, भूमि का किराया बाजार निर्धारण आधार पर वसूल करेगा और ऐसे मूल्य पर रेलवे कोई नियंत्रण नहीं रखेगी।
- (15) सभी परिचालनिक अंतर्देशीय कंटेनर डिपो में शंटिंग, स्थानन, हटाना, विरचना ऑपरेटर के निवेदन पर किए जाएंगे और वह ऐसी सेवाओं के लिए ऑपरेटर तथा रेल के बीच किए गए करार के अनुसार संदाय करेगा।
- (16) रेल द्वारा डेमरेज प्रभार नहीं लगाया जाएगा, परंतु रेल ऑपरेटर से संबंधित चल स्टॉक भारतीय रेल नेटवर्क पर खड़ा रहता है तो उस पर समय-समय पर अधिसूचित दरों के अनुसार खड़े रहने का प्रभार लगाया जाएगा।
- (17) रेल ऑपरेटर एक सामान्य वाहक होगा जैसाकि अधिनियम में परिभाषित किया गया है।
- (18) अधिनियम के अनुसार दावों के लिए सामान्य नियम लागू होंगे।

13. कंटेनर गाड़ियां प्रचालन के लिए अनुज्ञा की विधिमाम्यता की अवधि.—(1) अनुज्ञा की विधिमाम्यता ऑपरेटर द्वारा कंटेनर गाड़ियां चलाए जाने की तारीख से बीस वर्ष की अवधि के लिए होगी और अनुज्ञा की विधिमाम्यता समाप्त हो जाने के पश्चात् संतोषप्रद अनुपालन के अधीन इसे उसी पक्षकार के आवेदन पर तथा उस समय लागू फीस, जिसका विनिश्चय रेलवे बोर्ड द्वारा किया जाएगा, के अधीन दस वर्षों के लिए आगे बढ़ाया जा सकेगा।

- (2) किसी ऑपरेटर को इस व्यवसाय से बाहर निकलने की अनुज्ञा होगी या कंटेनर गाड़ियां प्रचालन के लिए किसी अन्य ऑपरेटर को अनुज्ञा हस्तांतरित करने की अनुज्ञा होगी, बशर्ते दूसरा ऑपरेटर इन नियमों के अधीन अधिकथित अनुज्ञा के लिए शर्तों को पूरा करता हो और रेल मंत्रालय से पूर्विक अनुमोदन के अधीन भी हो तथा यह अनुज्ञा उसकी अंतर्देशीय कंटेनर डिपो से रेलवे द्वारा जारी कंटेनर यातायात आरंभ किए जाने के एक वर्ष बाद ही मिलेगी।

14. अनुज्ञा रद्द करना तथा विवादों का निपटारा.—(1) ऑपरेटर वहन किए जाने वाले माल की या रेलवे संपत्ति की संरक्षा के लिए रेलवे द्वारा अधिकथित नियमों या कंटेनरों के संचलन के लिए सरकार द्वारा अधिकथित किसी भी नियम का पालन नहीं करता, तो एक महीने की सूचना देकर ऑपरेटर की अनुज्ञा को रद्द किया जा सकता है तथा वह अधिनियम के अनुसार शास्तियों के लिए दायी हो सकेगा।

- (2) ऑपरेटर द्वारा कंटेनर गाड़ियों के परिचालन को अनुज्ञा की अवधि से पूर्व समाप्त करना चाहने की दशा में, वह तीन मास की सूचना देकर रेल मंत्रालय को लिखित रूप में आवेदन करेगा।
- (3) अनुज्ञा रद्द किए जाने पर, पक्षकार को रजिस्ट्रीकरण फीस का कोई भाग वापिस नहीं होगा।
- (4) अंतर्देशीय कंटेनर डिपो के लिए साइडिंग से संबंधित, नुकसानी के लिए दावा, कर्षण प्रभारों, के विवादों के समाधान के लिए, साइडिंग करार से संबंधित उपबंधों का आश्रय लेकर रेल दावा अधिकरण या रेल दर अधिकरण से भी प्रतिरोध कर सकेगा।

[फा. सं. 2002/टीटी-III/15/39(पॉलिसी)]

आर. के. टंडन, कार्यपालक निदेशक, यातायात परिवहन (एफ)

MINISTRY OF RAILWAYS

(RAILWAY BOARD)

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th September, 2006

G.S.R. 593(E).—In exercise of the powers conferred by Section 198 of the Railways Act, 1989 (24 of 1989), the Central Government hereby makes the following rules, namely:—

1. Short title and commencement :—

(1) These rules may be called the Indian Railways (permission for operators to move container trains on Indian Railways) Rules, 2006.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.—In these rules, unless the context otherwise requires—

- (a) “Act” means the Railways Act, 1989 (24 of 1989);
- (b) “Operator” means a person who has taken permission to run container trains on Indian Railways.
- (c) All other words and expressions used in these rules and not defined, but defined in the Act shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

3. Eligibility.—Any person individual or a joint venture or a company registered under the Companies Act, 1956 shall be eligible to obtain the permission to operate container trains under these rules.

4. Export-Import Traffic.—For export-import traffic the operator shall

- (a) have a suitable access to a rail linked Inland Container Depot with adequate handling capacity in the hinterland or inland location for handling of container trains; or
- (b) enter into an agreement with an existing rail Inland Container Depot operator or rail terminal operator for using his facility for container train

operations, within six months of obtaining in principle approval from Ministry of Railways; or

- (c) give an undertaking that he shall develop his own Inland Container Depot with rail facility within a period of three years from the date of obtaining in principle approval to operate container trains.

5. Domestic Traffic.—For Domestic traffic the operator shall

- (a) have a suitable access to two rail linked Inland Container Depots with adequate handling capacity in two hinterland or inland locations for handling of container trains; or
- (b) enter into an agreement with an existing rail Inland Container Depot operator or rail terminal operator for using his facility at two locations for container train operations, within six months of obtaining in principle approval from Ministry of Railways; or
- (c) give an undertaking that he shall develop his own Inland Container Depot with rail facility at two locations within a period of three years from the date of obtaining in principle approval to operate container trains.

6. The applicant shall have experience in any of the following activities namely :—

- (i) Transport;
- (ii) Trade and Commerce;
- (iii) Infrastructure;
- (iv) Handling of Goods/Cargo;
- (v) Port/Land Terminal operations;
- (vi) Logistics;
- (vii) Warehousing;
- (viii) Manufacturing;
- (ix) Leasing.

7. Regulation of Rail Container Operations.—In order to regulate the entry of rail container operators on Indian Railway network, various routes have been grouped into four categories largely based on the existing as well as anticipated traffic volumes on different rail corridors serving gateway ports and these categories are as follows:—

- (1) **Category I**—includes all existing or future Inland Container Depots serving J.N. Port or Mumbai Port in National Capital Region like Tughlakabad, Dadri, Gurgaon and shall also include all destinations reached via National Capital Region like Dhandari Kalan, Moradabad along with all domestic traffic.
- (2) **Category II**—includes all existing or future Inland Container Depots serving J.N. Port or Mumbai Port at locations other than those covered in Category I along with all domestic traffic except on traffic routes mentioned in Category-I.

- (3) **Category III**—includes all existing or future Inland Container Depots serving the ports of Pipava, Mundera, Chennai, Ennore, Vizag and Kochi and their hinterlands along with all domestic traffic except on traffic routes mentioned in Category-I.
- (4) **Category IV**—includes the ports like Kandla, New Mangalore, Tuticorin, Haldia, Kolkata, Paradip and Mormugao and their hinterland along with all domestic traffic except on traffic routes mentioned in Category-I.

8. Financial capability.—(1) The applicant shall have the financial capability of an annual turnover or the net worth of not less than rupees one hundred crores.

- (2) In case a number of companies form a consortium for the purpose of operating container trains, each constituent member shall have either annual turnover or net worth of not less than rupees fifty crores.
- (3) Any company which has been declared sick under Sick Industrial Companies (Special Provision Act, 1985) shall not be eligible to apply under these rules to operate container trains either individually or in association with other companies.

9. Approval Process.—(1) If the proposed operator has to develop Inland Container Depot then for rail linking an Inland Container Depot, he shall obtain the requisite permissions from the Inter-Ministerial Committee of the Government of India within six months for developing and operating Inland Container Depot.

- (2) He shall submit his application to Ministry of Railways indicating therein his legal identity, intended scope of operations for atleast next five years, proof of complying with various eligibility criteria and his willingness to abide by the terms and conditions laid down in these rules and as amended from time to time.
- (3) Based on the documents furnished and clarification, if any, Railways shall grant an 'in principle' approval and in case the prospective operator fails to indicate his readiness to operate his container trains to the satisfaction of Railway within three years of grant of 'in principle approval', it shall be deemed to have lapsed unless prior extension is given by Railways.
- (4) Before commencing operations, the operator shall enter into an agreement with the Railways containing the detailed operating and accounting procedure, including the ownership of the new lines or assets and other relevant details and the agreement shall have provisions for suitable arbitration procedure for resolving any dispute between Railways and the operators.
- (5) The permission shall be open for one month in every year.

10. Registration Fee.—(1) At the time of submission of application to run container trains, every applicant shall be required to deposit a non-refundable registration fee of rupees fifty crores for applying for all categories of routes including Category-I and rupees ten crores for each individual category of routes except Category-I and the application only for routes mentioned in Category -I shall not be accepted.

- (2) The registration fee of applicants, who are not found eligible shall be refunded without any interest.

11. Modalities of granting permission.—(1) Permission for Category-I, shall include permission to run trains between any pairs of points in the entire country and shall include permission for all other categories and in case the operator applies for a particular category (except for Category -I), he shall obtain permission to run container trains between any pairs of points in that category only for export-import traffic and for all routes in domestic traffic, except those mentioned in Category-I.

- (2) There shall be no limit on number of trains on any of the routes.

12. Terms and conditions.—(1) The container trains of various operators shall normally be dispatched on a non-discriminating manner on 'first come first served' basis, subject to any operational exigencies and/or restrictions from time to time.

- (2) Inland Container Depots shall be treated like private sidings with the extant rules and procedures laid down for private sidings applying *mutatis-mutandis* to them.
- (3) Land and other related facilities required for railway operation and the track connecting the Inland Container Depot to the nearest rail head shall have to be provided by the operator at his own cost; but if railway land is available, on the application of the operator the same shall be provided on the normal terms and conditions laid down by Ministry of Railways for licensing of Railway Lands.
- (4) For movement of containers, the operator shall procure his own rolling stock and containers according to the approved design of the Research Design and Standard Organization and the rolling stock shall be inspected as per rules in force.
- (5) Loading and unloading of containers in the ports or Inland Container Depots shall be the responsibility of the operator.
- (6) Maintenance of track shall be done by the operator at his own cost, with Indian Railways being paid the charges for inspection or supervision according to the prescribed prevailing rates and maintenance of rolling stock shall be done by Indian Railways, for which the prescribed charges shall be recovered from the operator.

- (7) The operator shall allow Indian Railways to enter into any of its premises for inspection and for scrutiny of documents pertaining to rail-related operations and shall provide necessary and reasonable facilities for doing so.
- (8) The operator may carry all goods subject to conditions specified in the goods tariff, red tariff, and under the provisions of the Act and any other instructions issued on the subject by Ministry of Railways from time to time.
- (9) The movement of containers or flats shall only be in block rakes of prescribed standard sizes for different types of wagons as notified by the Railways from time to time.
- (10) Freight Operation Information System of Indian Railways shall also cater to the requirements of the operator for an integrated management and operations information service and the operator shall provide all relevant data as required by Freight Operation Information System and shall be given 'read only' access to this system on payment of reasonable cost.
- (11) The operator shall pay to the railways haulage charges applicable uniformly to all operators, as notified or fixed by the Railways from time to time.
- (12) For payment of haulage charges the provisions of Commercial Manual and other guidelines issued from time to time shall be followed.
- (13) Documentation work, including issue of Railway Receipt for haulage charges shall be done by Railway staff posted by Railways in the Inland Container Depot and the cost of such staff shall be borne by the operator and shall be charged separately.
- (14) The operator shall charge his customers for rail haulage, terminal handling, ground rent on a market determined basis and railways shall not exercise any control over such pricing.
- (15) All operations like shunting, placement, withdrawal, formation within the Inland Container Depot shall be done on the request of the operator and he shall pay for such services, as per the agreement signed between the operator and the Railway.
- (16) There shall be no demurrage charges by the Railway, but the Railway shall levy stabling

charges as per the rates notified from time to time in case rolling stock belonging to the operator is stabled on Indian Railways network.

- (17) The rail operator shall be a common carrier as defined under the Act.
- (18) Normal rules in respect of claims shall be applicable according to the Act.

13. Period of validity of permission for operating container trains.—

(1) The validity of permission shall be for a period of twenty years from the date of operation of container trains by the operator and the permission can be extended by ten years to the same party on his application after expiry of the validity of permission subject to satisfactory performance and on payment of the fees as applicable at that time, to be decided by Railway Board.

- (2) An operator may be permitted to exit from the market or transfer the permission to another operator for container train operation, subject to the latter fulfilling the conditions for permission mentioned under these rules and also subject to prior approval of the Ministry of Railways and the permission shall be granted only one year after rail borne container traffic has commenced its operation from his Inland Container Depot.

14. Cancellation of the permission and dispute settlement.—

(1) In case the operator does not follow the rules laid down by Railways for safety of goods carried or of railway property or any rules laid by the Government for movement of containers, the permission of the operator may be cancelled by giving one month's notice and he may also be liable to be penalized in accordance with the Act.

- (2) In case the operator wants to terminate operation of container trains before the expiry of permission period, he shall give the request in writing to the Ministry of Railways with three months notice.
- (3) On cancellation of the permission, no part of the registration fee shall be refunded to the party.
- (4) For resolving disputes on the issues pertaining to the siding for the Inland Container Depot, claims for damages, haulage charges, the operator may also seek redressal by resorting to the relevant provisions of siding agreement, Railway Claims Tribunal or Railway Rates Tribunal.

[F.No.2002/TT-III/15/39 (Policy)]

R. K. TANDON, Exec. Director, Traffic Transportation
(F)